



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

AC
23/9

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2002/वैशाख 10, 1924

No. 194]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2002/VAISAKHA 10, 1924

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2002

सा.का.नि. 309(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0 साठोनिं 556(अ) तारीख 26.7.2001 को उन बातों के सिवाय, अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि—

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसी निधि या ऐसी पारस्परिक फायदा सोसाइटी कहा गया है) के रूप में घोषित की गई प्रत्येक कंपनी, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् राजस्व की मान्यता और बंधक ऋण या आभूषण ऋण आदि के संबंध में आस्तियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(i) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर आय को, जिसमें ब्याज या अन्य कोई प्रभार भी सम्मिलित है, केवल तभी मान्यता दी जाएगी, जब इसकी वास्तविक वसूली हो जाएगी। ऐसी कोई आय, जिसे आस्तियों के गैर-निष्पादनकारी बनने से पूर्व मान्यता दी गई है और जिसकी वसूली नहीं की गई है, चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखा में प्रतिवर्तित की जाएगी।

(ii) आस्तियों का वर्गीकरण(क) "बंधक ऋण :

| आस्ति की प्रकृति | अपेक्षित उपबंध |
|------------------|------------------------------|
| मानक आस्ति | कोई उपबंध नहीं |
| अवमानक आस्ति | कुल बकाया रकम का 10 प्रतिशत |
| संदेहजनक आस्ति | कुल बकाया रकम का 25 प्रतिशत |
| हानि आस्ति | कुल बकाया रकम का 100 प्रतिशत |

स्पष्टीकरण— इस निदेश में-

(1) “मानक आस्ति” से ऐसी अस्ति अभिप्रेत है, जिसकी बाबत मूल के प्रतिदाय या व्याज के संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है और जिसमें न तो कोई समस्या प्रकट हुई है और न ही उसमें कारबाह से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम है;

(2) “अव-मानक आस्ति” ऐसा चालार संबंध लेखा जो गैर-निष्पादनकारी आस्ति है। ऋण की किस्त या व्याज के प्रतिदाय का पुनः नियतन या पुनः पारक्रामण या रिफेन्मेंट, तब तक आस्तियों के वर्गीकरण को परिवर्तित नहीं करेगा जब तक कि उधार संबंधी लेखा, ऐसे पुनःनियतन या पुनःपारक्रामण या रिफेन्मेंट के पश्चात् कम से कम 12 मास तक समाधान प्रद रूप में निष्पादित न किया गया हो;

(3) “सदैहजनक आस्ति” ऐसे चालार संबंधी लेखे होंगी जो दो वर्ष से अधिक के लिए किन्तु तीन वर्ष तक गैर-निष्पादनकारी बने रहे हैं;

(4) “हानि आस्ति” ऐसे उधार संबंधी लेखे होंगी जो तीन वर्ष से अधिक गैर-निष्पादनकारी बने रहे हैं या जहां निधि या उसके आतंरिक लेखा परीक्षक या उसके निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उनके बारे में यह राय है कि ऋण लेखे में वसूली में कभी निष्पादित दस्तावेज विधिक प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए या किसी अन्य कारण से अविधिमान्य होने के कारण आई है;

(5) “गैर-निष्पादनकारी आस्तियाँ” ऐसे उधार संबंधी खाते होंगी, जहां व्याज आय और / या मूल रकम के प्रति ऋण की किस्त का प्रतिदाय 12 मास से वसूला नहीं गया है:

परन्तु यह कि ऐसी निधि कंपनी या पारस्परिक फायदा सोसाइटी, जो 26.7.2001 को या उसके पूर्व निर्गमित की गई हैं, नीचे दी गई सारणी के अनुसार विवेकपूर्ण मानों का पालन करेंगी :

सारणी

| निम्नलिखित तारीखों तक दिए गए बंधक ऋण और उन तारीखों को बकाया | अनुपालन की तारीख अर्थात् तुलन पत्र की तारीख |
|---|---|
| (क) 31.3.2000 | 31.3.2005 |
| (ख) 31.3.2001 | 31.3.2006 |
| (ग) 31.3.2002 | 31.3.2007 |

(ख) आभूषण, सरकारी प्रतिभूतियों या स्वयं के निक्षेपों, आदि के प्रति ऋण—

स्वर्ण, आभूषणों, आदि प्रतिभूतियों के प्रति मंजूर किए गए ऋण की कुल बकाया रकम ऐसे ऋणों की मंजूरी के समय विनिर्दिष्ट की गई प्रतिनिधित्व की नियत तारीख से अगले तीन मास के भीतर या तो वसूल की जानी चाहिए या उसका नवीकरण किया जाना चाहिए। यदि दिए गए समय के भीतर ऋण की वसूली नहीं की जाती है या प्रतिभूति का विक्रय नहीं किया जाता है, कंपनी को यथा लागू वसूल न की गई रकम या कुल बकाया रकम की सीमा तक चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखे के प्रति शत प्रतिशत वसूली करने का उपबंध किया जाना चाहिए। बकाया रकम के तीन मास की अवधि के पश्चात् या आभूषणों के विक्रय के पश्चात् जो भी पूर्वतर हो, ऐसे ऋणों पर किसी आय को मान्यता नहीं दी जाएगी।

2. राजस्व मान्यता और आस्तियों के वर्गीकरण के लिए उपर्युक्त विवेकपूर्ण मान इस अधिसूचना के पूर्व या पश्चात् कंपनी अधिनियम, 1956 की द्वारा 620क के अधीन अधिसूचित सभी निधि कंपनियों या पारस्परिक फायदा सोसाइटीयों को लागू होंगे।

3. केन्द्रीय सरकार का, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियों उद्भूत हो गई हैं और लोक हित में यदि ऐसा पाया जाता है, लिखित में कारण अभिलेखित करने के पश्चात् या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसे केन्द्रीय सरकार किसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी या निधियों के वर्ग या पारस्परिक फायदा सोसाइटियों के वर्ग को किसी कठिनाई से बचाने के लिए विनिर्दिष्ट करे, ऊपर वर्णित निदेशों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. 5/7/2000-सी.एल.-5]
राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2002

G.S.R. 309(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 637 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of Notification of the Government of India, Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Department of Company Affairs) No GSR 556(E) dated 26.7.2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that-

1. Every company declared as a Nidhi or Mutual Benefit Society under section 620A of the Companies Act, 1956 (hereinafter referred to as such Nidhi or Mutual Benefit Society) after the publication of this Notification shall adhere to the following prudential norms for revenue recognition and classification of assets in respect of mortgage loans or jewel loans, namely:-

- (i) income including interest or any other charges on non-performing assets shall be recognised only when it is actually realised. Any such income recognised before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed in the current year's profit and loss account;

(ii) Classification of assets**(a) Mortgage Loan:**

| NATURE OF ASSET | PROVISION REQUIRED |
|---------------------------|--|
| Standard Asset | No provision |
| Sub-standard Asset | 10% of the aggregate outstanding amount |
| Doubtful Asset | 25% of the aggregate outstanding amount |
| Loss Asset | 100% of the aggregate outstanding amount |

Explanation: In this direction,-

- (1) “**Standard Asset**” means the asset in respect of which no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem nor carry more than normal risk attached to the business;
- (2) “**Sub-Standard Asset**” will be that borrowing account which is a non performing asset. Reschedulement or Renegotiation or Rephasement of the loan instalment or interest payment would not change the classification of assets unless the borrowing account has satisfactorily performed for at least 12 months after such reschedulement or renegotiation or rephasing;

- (3) “**Doubtful Asset**” will be that borrowing account which remained non-performing for more than two years but up to three years;
- (4) “**Loss Asset**” will be that borrowing account which remained non-performing for more than three years or where as per the opinion of the Nidhi or its internal auditor or by the inspecting authority during the course of its inspection a shortfall in the recovery of the loan account is expected because the documents executed may become invalid if subjected to legal process or for any other reason;
- (5) “**Non-Performing Asset**” will be that borrowing account where interest income and/or instalment of loan towards repayment of principal amount remained unrealised for 12 months:
- “**provided** that the Nidhi companies or Mutual Benefit Societies incorporated on or before 26.7.2001 shall adhere to the prudential norms as per table given below:

TABLE

| Mortgage loans given up to and outstanding as on | Compliance date i.e. date of the balance sheet |
|---|---|
| (a) 31.3.2000 | 31.3.2005 |
| (b) 31.3.2001 | 31.3.2006 |
| (c) 31.3.2002 | 31.3.2007 |

(b) Loans against Jewellery, Government Securities or own deposits, etc.,

The aggregate outstanding amount of loan granted against the security of gold, jewellery etc., should be either recovered or renewed within next three months after the due date of repayment specified at the time of grant of such loans. If the loan is not recovered or the security is not sold within the given time, the company should make 100% provision against current year's Profit and Loss Account to the extent of unrealised amount or aggregate outstanding amount of loan as applicable. No income shall be recognised on such loans outstanding after the expiry of three months period or sale of jewellery, whichever is earlier.

2. The above prudential norms for revenue recognition and classification of assets shall be applicable to all Nidhi companies or Mutual Benefit Societies notified under section 620 A of the Companies Act, 1956 before or after the publication of this notification.

3. The Central Government if satisfied that the circumstances have arisen and if found in public interest, after recording the reasons in writing, may relax any of the directions mentioned above either generally or for any specified period, subject to such terms and conditions, as that Government may specify, for avoiding any hardship to any Nidhi or any Mutual Benefit Society or class of Nidhis or class of Mutual Benefit Societies.

[F. No 5/7/2000-CL-V])

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.